साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 16-22 अक्टूबर 2023 वर्ष-9, अंक-27
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

किसान परेशानः समर्थन मूल्य से भी नीचे बिक रही उपज

सोयाबीन के घटे दाम

-मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र के किसानों की ओर से उठ रही मांग

भोपाल। जागत गांव हमार

सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4600 रुपए क्विंटल है। इन दिनों में मंडी में आ रहा नया सोयाबीन 4400 से 4600 रुपए क्विंटल के दाम पर बिक रहा है। सोयाबीन के घटे दामों ने खरीफ में सोया उपजाने वाले किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। किसान नाराज हं और औद्योगिक संगठनों ने किसानों का साथ देने के लिए आवाज उठाई है। दो वर्ष पहले सोयाबीन 10 हजार प्रति क्विंटल के दाम तक भी बिका था। यह सोयाबीन का उच्चतम दाम था। इसके पहले के वर्षों में सोयाबीन की कीमत 5200 से 7000 रुपए रही है। इस साल सबसे ज्यादा गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश देश का शीर्ष सोया उत्पादक राज्य है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। ऐसे में दोनों प्रदेशों से अब किसानों की ओर से मांग उठ रही है।

मध्य प्रदेश में सोपा ने इस वर्ष 52.46 लाख टन आंका है। उत्पादन हालांकि बीते वर्ष से थोड़ा कम है लेकिन फिर भी कीमतें गिरी हुई हैं। सोपा के अनुसार, देश में इस साल चुनावी वर्ष होने के कारण सरकार की पूरी कोशिश खाद्य पदार्थों की महंगाई नियंत्रित करने की रही। इसके चलते सरकार ने शून्य ड्यूटी पर खाद्य तेल आयात की अनुमति दी। नतीजा ये हुआ कि इस साल देश में 42 लाख टन तेल आयात हो चुका है, जो बीते वर्ष से करीब 10 लाख टन ज्यादा है। जरुरत से ज्यादा आयात का नतीजा ये रहा कि अब देश में उत्पादित सोयाबीन और सोया प्रोसेसर्स पर दबाव है।

सोयाबीन आयात पर ड्यूटी बढ़ाए सरकार

सोयाबीन के दाम मंडियों में 4400-4500 रुपए क्विंटल रह गए हैं। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 4600 से भी कम है। सरसों का भी 113 लाख टन उत्पादन हुआ है। यदि दाम नीचे बने रहे तो अगले साल किसान सोयाबीन बोने से कदम पीछे खींच लेंगे नतीजा होगा कि देश खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य से पिछड़ जाएगा। सरकार को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य तक पहुंचना है तो तुरंत खाद्य तेलों के आयात पर कम से कम 30 प्रतिशत ड्यूटी लगाना चाहिए जो फिलहाल 5 प्रतिशत ही है। मंडियों में आठ लाख बोरी तक सोयाबीन पहुंच रहा है। दाम गिरे तो किसान माल रोकने लगेंगे। इससे प्रोसेसर्स की परेशानी बढ़ेगी।

प्रदेश में इस साल उत्पादन में कमी की आशंका

इधर, सोपा की मेजबानी में इंदौर में हुए अंतरराष्ट्रीय सोया 2023 कान्क्लेव में खरीफ 2023 सीजन में सोयाबीन फसल को लेकर सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई। बुवाई क्षेत्रफल बढ़ने के बावजूद सोया के उत्पादन में गिरावट की आशंका जताई गई है। पहले कम बारिश और फिर अतिवर्षा के कारण उत्पादकता पर असर पड़ने की आशंका जताई है। खरीफ 2023 सीजन में सोया उत्पादन 118.74 लाख टन आंका गया है, जबकि बीते खरीफ सीजन में 124.11 लाख टन था। खरीफ 2023 में उत्पादकता 1002 किलो प्रति हेक्टेयर बताई गई जो खरीफ 2022 में 1084 किलो प्रति हेक्टेयर थी। मध्य प्रदेश में सोया उत्पादन 52.46 (गत वर्ष 54.13), महाराष्ट्र में 46.92 (गत वर्ष 49.25) व राजस्थान में 10.124 (गत वर्ष 10.348) लाख टन के आकड़े दिए गए। तेलंगाना को छोड़ अन्य सभी राज्यों में सोया उत्पादन गत वर्ष से कमजोर रहा। इस साल बारिश होने और नहीं होने से भी उत्पादक जिलों में किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

हरदा में में 15497 मी.टन यूरिया, 12597 मी.टन डीएपी आया

खाद की बोरियों पर मोदी की फोटो, अब थिनर से मिटाएंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

कृषि मंत्री कमल पटेल के गृह जिला हरदा में खरीफ सीजन की कटाई के अंतिम दौर के साथ रबी सीजन की बोवनी की तैयारियां शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव के बीच अधिकारी खाद वितरण की व्यवस्था में लगे हैं। लेकिन दो दिनों से किसानों को खाद की सप्लाई अचानक रोक दी है। इसका कारण यह है कि आचार संहिता के बीच यूरिया और पोटाश की बोरी पर पीएम नरेंद्र मोदी के फोटो प्रिंट है। वहीं डीएपी पर भरतीय जन उर्वरक परियोजना (भाजपा) लिखा होने पर इसे आचार संहिता के उल्लंघन मानते हुए जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन विश्नोई ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से इसकी शिकायत की है। इसके बाद प्रशासन ने किसानों को यूरिया की सप्लाई रोक दी है। अब प्रशासन ने पीएम के फोटो को थिनर से मिटाने का निर्णय लिया है।

ऑनलाइन एंट्री के बाद वितरण होगा

खुले बाजार में बोरियां पहुंच चुकी हैं, लेकिन दुकानदार उन्हें बेच नहीं रहे हैं। इनमें फोटो वाली 1 हजार पोटाश की बोरी बाजार में हैं। जिले में 15497 मीट्रिक टन यूरिया यानी 25395 बोरी पीएम के फोटो वाली हैं। यह बोरियां डीएमओ डबल लॉक,जिले की सभी सोसाइटी और बाजार में खाद बीज दुकानों पर पहुंच चुकी हैं। अब इन पर प्रिंट फोटो को थिनर से मिटाया जाएगा। इसके बाद ऑनलाइन एंट्री के बाद वितरण होगा। वहीं 12597 मीट्रिक टन डीएपी आया है जिनकी बोरियों पर भरतीय जन उर्वरक परियोजना (बीजेपी) लिखा है। इस बार रबी सीजन में जिले में 191575 हेक्टेयर में बोवनी का अनुमान है।

भोपाल चुनाव आयोग तक पहुंची शिकायत

जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मोहन विश्नोई ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल को शिकायत की। इसमें उन्होंने कहा कि यूरिया, पोटाश सहित अन्य खाद की बोरियों पर पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो प्रिंट है। बोरियां डीएमओ डबल लॉक के अलावा खुले बाजार में भी मिल रही हैं। इसके अलावा डीएपी की बोरी में भारतीय जन उर्वरक परियोजना अंग्रेजी में लिखा है। इसका शार्ट फार्म बीजेपी हो रहा है। उन्होंने इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

समूह का टर्नओवर एक करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचा

आदिवासी महिलाओं ने मजदूरी छोड़ शुरू किया मुर्गी पालन

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

आदिवासी महिलाओं ने मिसाल पेश की है। बड़ी संख्या में महिलाएं मजदूरी छोड़कर चिकन प्रोडक्शन में हाथ आजमा रही हैं। नर्मदापुरम के केसला की आदिवासी महिलाएं इस काम से लाखों रुपए कमा रही हैं। इन आदिवासी महिलाओं का सबसे बड़ा समूह केसला पोल्ट्री सहकारी समिति से जुड़कर लगभग 20 वर्षों से चिकन प्रोडक्शन का काम कर रहा है। यह कुल 1278 महिलाओं का एक समूह है। इन महिलाओं ने अपनी आजीविका को बेहतर तो किया ही है। साथ ही बच्चों की अच्छी शिक्षा पर भी जोर दिया है।

कुंती धुर्वे ने आगामी वर्ष 2023-24 की कार्य योजना बताते हुए कहा इस वर्ष 16 लाख 10 हजार चूजा डालने की योजना है। इस वर्ष में मुर्गी का औसत वजन 2.23 किलोग्राम हम बेचेंगे। इस वर्ष 2.23 किलोग्राम वजन पालकर 1.65 एफसीआर का लक्ष्य रखा है। इस वर्ष मुर्गी को औसत दिन 38.8 में बेचेंगे। इस वर्ष सहकारिता का व्यवसाय लगभग 32.62 करोड़ रुपए और सहकारिता के सदस्यों का मुनाफा लगभग दो करोड़ रुपए करने का लक्ष्य है।

1278 महिलाओं का समूह

नर्मदापुरम के केसला ब्लाक में पोल्ट्री सहकारी सोसाइटी की अध्यक्ष कुंती धुर्वे ने बताया है कि हमारा समूह मुर्गी उत्पादन के क्षेत्र में देश में सबसे बड़ा है। सहकारिता की गत वर्ष के अन्त में कुल सदस्य 1258 थी, लेकिन इस वर्ष में 20 नई महिला सहकारिता की सदस्य बनी हैं। इस तरह सहकारिता की कुल 1278 महिलाओं का समूह हो गया है। कुंती ने कहा कि गत वर्ष सहकारिता की अंश पूंजी 1 करोड़ 14 लाख 69 हजार 600 रुपए थी, लेकिन अब बढ़कर 1 करोड़ 25 लाख 57 हजार रुपए से ज्यादा हो गई है।

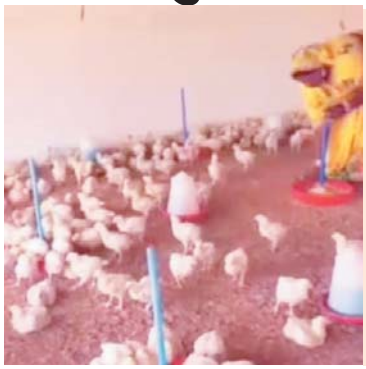

सब्जी उत्पादन भी कर रहीं महिलाएं

चिकन प्रोडक्शन कर रही महिला सुनीता बाई और रमेती बाई ने जानकारी दी कि पहले वह मजदूरी करने जाती थी। मजदूरी से मुश्किल परिवार का भरण पोषण हो पाता था, लेकिन, अब उन्होंने मजदूरी छोड़ कर चिकन प्रोडक्शन के साथ ही सब्जी उत्पादन का काम शुरू किया है। इसके कारण अब हर साल उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। इस आमदनी से उनका घर बहुत अच्छा चल रहा है।

केसला ब्लाक में महिलाएं मुर्गी पालन में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इससे न केवल उनकी आजीविका बढ़ी है, बल्कि महिलाएं आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रही हैं। महिलाएं पहले मजदूरी का काम करती थीं, लेकिन, अब मजदूरी का काम छोड़कर मुर्गी पालन में बेहतर काम कर रही हैं। जिससे उनकी आमदनी कई गुना बढ़ी है। साथ ही वह अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दे रही हैं।

डॉ. हरे कृष्ण डेका, कार्यपालन अधिकारी केसला ब्लाक

वन मंत्री शाह ने दिया था महंगे छाते खरीदी का सुझाव, निजी कंपनियों को हो जाता 10 करोड़ रुपए का फायदा

चरण पादूका योजना में सामने आया खरीदी का घोटाला

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री चरण पादूका योजना के तहत प्रदेश के 15.24 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों को जूता-चप्पल, साड़ी, पानी की बोतल और छाता वितरण पर करीब 261 करोड़ रुपए खर्च किए। छाता वितरण के लिए सरकार ने ऐन मौके पर 200 रुपए की राशि संग्राहकों के खाते में जमा करने का फैसला लिया, लेकिन इसके पीछे कुछ अधिकारियों का दबाव भी रहा। जिन्होंने महंगे छातों की खरीद रोक दी। यदि मंत्री की सिफारिश मान ली जाती तो राज्य लघु वनोपज संघ को करीब 10 करोड़ का नुकसान होता। राज्य लघु वनोपज संघ ने योजना के तहत छाता वितरण के लिए मार्च में पहली निविदा जारी की थी। इसमें करीब 10 कंपनियों ने हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। मई में दूसरी बार टेंडर जारी किया गया, जिसमें करीब 246 रुपए का रेट मिला। रेट ज्यादा होने पर खरीदी के लिए बनाई गई लघु उद्योग निगम की कमेटी ने तीसरी बार टेंडर जारी किया तो रेट घटकर 209 रुपए हो गया। तीसरी बार में तीन कंपनियां इसमें सिलेक्ट की गई। कमेटी से जुड़े अफसरों ने जब मार्केट सर्वे कराया तो निविदा करने वाली एक कंपनी का वही छाता सिर्फ 140 रुपए में मिल रहा था। वहीं वन मंत्री से जब नोट शीट के बार में पूछा तो मंत्री ने नोट शीट लिखने से साफ इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो किया अफसरों ने ही किया। मैंने तो कोई नोटशीट ही नहीं लिखी।

आचार संहिता का दिया हवाला

कमेटी ने स्नैप बिडिंग की गई तो तीनों कंपनियों ने चार ग्रुप बनाकर 190 रुपए का रेट डाला। बोर्ड के एमडी ने अपनी टिप में प्राप्त दर को अधिक बताते हुए शासन से मार्गदर्शन मांगा। इसमें लिखा गया कि तीन माह में अब प्रक्रिया को पूरा कर पाना संभव नहीं होगा और आचार संहिता लग जाएगी। मंत्री ने टिप लिखी कि विभाग का नाम छातों पर लिखा जाए और 200 प्लस जीएसटी से कम दर है तो आदेश देकर 60 दिन में कार्यवाही पूरी की जाए।

खरीदी होती तो वितरण ही नहीं हो पाता

प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बाजार में जो छाता न्यूनतम 145 रुपए प्रति नग में मिल रहा था, वह इतने ऑर्डर पर 120 से 130 रुपए तक आसानी से मिल जाता। यदि जुलाई में ऑर्डर जारी किए जाते तो अगस्त अंत तक छाते मिल पाते। नियमानुसार 15 दिन प्री डिलेवरी टेस्टिंग और 15 दिन पोस्ट डिलेवरी टेस्टिंग के लिए होते हैं। ऐसे में अक्टूबर में आचार संहिता से पहले वितरण का काम शुरू नहीं हो पाता। लघु उद्योग निगम ने इस सिफारिश को नहीं माना।

चरण पादुका योजना के तहत जूते-चप्पल पानी बोतल, छाता और साड़ी सभी वस्तुओं की खरीद में करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ है। एक छाता जो बाजार में उसी कंपनी 140 रुपए में बेच रही है, उसके लिए 246 रुपए ये खरीद भाव तय किया गया। बाद में विभिन्न विरोधों के बाद भी उसको घटाकर 200 रुपए में खरीदा गया। जूते-चप्पल पानी बोतल, छाता और साड़ी खरीदी प्रकरण को देखा जाए तो कम से कम 50 से 60 करोड़ का भ्रष्टाचार सामने आया है।

आलोक शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता

रबी हो या खरीफ, हर बार यूरिया के लिए करनी पड़ रड़ती है मारा मारी

किसानों ने कहा- सरसों बेचकर मंडी से लौटे तब तक बंद हो गया काउंटर

यूरिया के लिए आधी रात से लाइन में लग रहे अन्नदाता

मुरैना। जागत गांव हमार

यूरिया खाद के लिए किसान सुबह चार बजे से लाइन में लगे तब दस बजे पर्ची मिली और अपनी फसल बेचने मंडी चले गए, लौटकर आए तो दो बजे काउंटर बंद कर कर्मचारी चले गए। जब किसानों ने हंगामा किया तो अधिकारियों के हस्तक्षेप के चलते दोबारा काउंटर खोला गया। नियमानुसार काउंटर सुबह दस बजे से शाम पांच बजे खुला रहना चाहिए लेकिन कर्मचारी दोपहर दो बजे काउंटर बंद कर चले गए जिससे किसान परेशान हुए। किसान सरसों की बोवनी के लिए खाद लेने गांव से शहर आए। पहले पर्ची के लिए पांच से छह घंटे लाइन में लगना पड़ा, पर्ची लेकर कुछ किसान अपनी फसल बेचने मंडी चले गए, जब फसल के दाम लेकर लौटे तो काउंटर बंद मिला। सरसों की बोवनी के लिए किसानों को यूरिया की आवश्यकता पड़ रही है। शहर में वितरण व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होने पर किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रबी की फसल हो या खरीफ की हर बार किसानों को यूरिया के लिए मारा मारी करनी पड़ती है। जितनी यूरिया की आवश्यकता है, उतना नहीं मिल रहा इसलिए किसानों को बार बार लाइन में लगना पड़ रहा है।

आवश्यकता दस कट्टे की, मिल रहे तीन- किसानों ने कहा कि हमको दस कट्टे चाहिए और यहां एक बार लाइन में लगने पर तीन कट्टे ही मिल रहे हैं। अगर ज्यादा कट्टे चाहिए तो बार बार लाइन में लगना होगा, तब यूरिया के कट्टे ले सकते हैं। व्यवस्था को लेकर किसानों का काफी नाराजगी जताई। उधर कुछ किसान सुबह चार से पांच बजे के आए, उनको पूरा दिन यूरिया लेने में ही निकल गया।

दो बजे काउंटर बंद, अधिकारी स्वयं पहुंचे मौके पर

कृषि उपज मंडी परिसर में जिला विपणन कार्यालय का काउंटर है। यहां दोपहर दो बजे काउंटर बंद करके कर्मचारी कहीं चले गए। किसान पर्ची लेकर पहुंचे तो काउंटर बंद देखकर भडक़ गए, उन्होंने हंगामा किया तो जिला विपणन अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को बुलाकर फिर से काउंटर खुलवाया, तब एक घंटे बाद किसानों को यूरिया मिल सका।

कृषि मंडी में डीएमओ के केंद्र से किसानों को यूरिया वितरित किया जा रहा है। दो बजे काउंटर बंद होने की मुझे जानकारी मिली तो मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, काउंटर दोबारा खुलवाया और जो किसान वहां खड़े थे, उनको यूरिया वितरित करवाया गया। हमारे यहां खाद की कोई कमी नहीं है।

शिशिर सिन्हा, जिला विपणन अधिकारी

क्या कहते हैं किसान

रात को तीन बजे आया था। सुबह दस बजे पर्ची लेकर मंडी चले गए। अनाज बेचकर आए तो दो बजे हमारे सामने काउंटर बंद कर दिया। हमने काफी निवेदन किया, लेकिन कर्मचारियों ने नहीं सुना। दो हजार भाड़े पर ट्रैक्टर लेकर आए।

रविन्द्र राजपूत, किसान

सुबह पर्ची लेकर हम अपनी फसल बेचने चले गए। मैंने अपना लड़का भी भेजा था कि मंडी में माल तुल गया है, अभी पैसे मिल रहे हैं, उसके बाद हम खाद ले जाएंगे लेकिन कर्मचारियों ने दो बजे काउंटर बंद कर दिया।

कमलेश सिंह, किसान

हमारी खेती के हिसाब से 25 कट्टे की आवश्यकता है। यहां घंटों लाइन में लगे तब तीन कट्टे की पर्ची मिली है। अब और कट्टे लेने हैं तो फिर से कई बार लाइन में लगना पड़ेगा, तब फसल की बोवनी में विलंब हो जाएगा।

गब्बर सिंह यादव, किसान

मैं वृद्ध आदमी हूं, सुबह पांच बजे इसलिए आया कि पहले लाइन में लग जाएंगे तो जल्दी पर्ची मिल जाएगी। पर्ची पांच घंटे लाइन में लगने के बाद मिली है। वह भी तीन कट्टे की और आवश्यकता दस कट्टे की है।

शंकर सिंह कुशवाह, किसान

उदासीनता के कारण छाया नहीं होने से धूप में काट रहे दिन

सड़कों से हटाए पशुओं को गौशालाओं में नहीं मिल रहा भूसा-चारा

भोपाल। जागत गांव हमार

राजधानी की सड़कों से गौवंश हटाने की कार्रवाई भले ही नगर निगम ने बंद कर दी, लेकिन जिन गोवंश को गौशालाओं और काजी हाउस में पहुंचाया गया, वो चारा और पानी नहीं मिलने से भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। साथ ही गौशालाओं में अचानक इतने जानवरों के पहुंचने से इनके रखने की जगह नहीं होने से दिनभर धूप में तपना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने गौशालाओं की हकीकत जानना भी जरूरी नहीं समझा।

पर्याप्त चारा-पानी की व्यवस्था भी नहीं- बता दें कि अरवलिया स्थित नगर निगम की गौशाला में मौजूद सैकड़ों गौवंश चारे के अभाव में तड़प कर मर रहे हैं। नगर निगम द्वारा यहां पशुओं को सही तरह से रखने के लिए पर्याप्त शेड तक नहीं बनवाए गए हैं, जिसके चलते छोटे बछड़े और बछिया तेज गर्मी में दिन भर धूप में बैठे रहते हैं।

हाल ही में गौसेवकों के एक दल ने बैरसिया स्थित अरवलिया ग्राम पंचायत के पतलोन ग्राम में पहुंचकर गौवंश की दुर्दशा पर नाराजगी जताई। गौशाला में बड़े पैमाने पर गोवंश छोड़े गए हैं, लेकिन उस हिसाब से यहां पर इनके भोजन की व्यवस्था नहीं की गई है। शहर में यातायात को बाधित करने वाले गौवंश को नगर निगम द्वारा पकड़कर बैरसिया विधानसभा की अरवलिया ग्राम पंचायत स्थित पतलोन ग्राम की गौशाला में पहुंचाया जाता है।

निरीक्षक दल ने जताया असंतोष

गौसेवकों का दल स्थानीय लोगों की शिकायत पर गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचा था। मौके का निरीक्षण करने पहुंचे एक गौसेवक ने बताया कि यहां पर नगर निगम द्वारा पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, लेकिन पिछले एक सप्ताह में किए गए सर्वे के दौरान उन्होंने पाया कि जानवरों को चारे की और ज्यादा उपलब्धता कराई जाना चाहिए।

निगम द्वारा गोशाला में पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है, रोजाना एक हजार बंडल से ज्यादा भूसा पहुंचाया जाता है, लेकिन हमारा प्रयास है कि पशु उचित मात्रा में ही आहार ग्रहण करें। यहां मौजूद 400 गायों को नियमित चारा दिया जा रहा है।

- विनय सोनी, प्रभारी गौशाला

-कृषि अवशेषों को जलाने से पिछले 10 सालों में गैस उत्सर्जन 75 फीसदी बढ़ा

आईसर के विज्ञानियों ने उपग्रह तकनीक से जाने कृषि अवशेष जलाने के नुकसान

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत में हर साल 87 मिलियन टन फसल के अवशेषों को जलाया जाता है। यह हमारे कई पड़ोसी देशों के कुल कृषि अपशिष्ट उत्पादन से भी अधिक है। देश के कुल कृषि अवशेषों के उत्सर्जन में 97 प्रतिशत योगदान धान, गेहूं और मक्के की फसल जलाने से होता है, जिसमें धान के अवशेषों का योगदान सबसे अधिक 55 प्रतिशत है। पिछले दशक में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक राज्यों में पंजाब और मध्यप्रदेश क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। यह तथ्य भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल (आईसर), अंतरराष्ट्रीय मक्का व गेहूं सुधार केंद्र हैदराबाद और अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के संयुक्त अध्ययन में सामने आए है। इस अध्ययन के लिए विज्ञानियों ने एक उपग्रह आधारित तकनीक को विकसित किया है जो भारत में जलाए जाने वाले कृषि अवशेषों से उत्पन्न होने वाली ग्रीन हाउस गैसों की जानकारी प्रदान करती है।

उपग्रह तकनीक ने बदली धारणा- इस अध्ययन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पूर्व अध्ययनों में यह माना गया था कि अगर खेती का उत्पादन ज्यादा होगा तो ज्यादा अवशेष जलाए जाएंगे, इसलिए अधिक उत्पादन करने वाले राज्यों में अधिक कृषि अवशेष जलाए जाने का अनुमान लगाया गया। इस अध्ययन में कृषि अवशेष जलाए जाने की सटीक जानकारी के लिए उपग्रह का इस्तेमाल किया गया। उपग्रह से अवशेष जलाए जाने वाले खेत नहीं जाने वाले खेतों से अलग

दिखते हैं। इससे यह पता चला कि यह मानना सही नहीं है कि जिन राज्यों में ज्यादा खेती होती है केवल वहीं ज्यादा कृषि अवशेष जलाए जाते हैं। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदि कई उत्पादक राज्य हैं, लेकिन इन राज्यों में कृषि अवशेष लगभग नहीं के बराबर जलाए जाते हैं। उपग्रह के उपयोग से इसे अच्छे से चिन्हित किया जा सका।

मप्र कृषि अवशेष जलाने वाले अग्रणी राज्यों में

विज्ञानियों के अनुसार मप्र में कुछ सालों में गेहूं की फसल अधिक उगाई जा रही है। इस कारण यहां पर कृषि अवशेष जाने की प्रक्रिया भी तेजी से बढ़ी है। यहां के किसान भी कृषि अवशेष हटाने के लिए उनमें आग लगाने का काम कर रहे हैं। मप्र में कई जिलों में भी अध्ययन किया गया। इसमें रायसेन, होशंगाबाद व उज्जैन जिले में अधिक कृषि अवशेष जलाए जा रहे हैं।

अध्ययन का निष्कर्ष

इस अध्ययन में पंजाब को सबसे अधिक ग्रीनहाउस उत्सर्जक क्षेत्र बताया गया है। वर्ष 2020 में इसके कुल कृषि क्षेत्र में से 27 प्रतिशत में कृषि अवशेष को जलाया गया। वहीं मध्यप्रदेश का स्थान दूसरा है जहां करीब 22 प्रतिशत अवशेष जलाए गए। वहीं वर्ष 2014-2015 में प्रभावी रूप से नीति क्रियान्वयन के कारण फसलों के अवशेषों के जलने में प्रारंभिक रूप से कमी आई थी, जबकि वर्ष 2016 में फिर से इसमें वृद्धि देखी गई है।

ढाई साल तक किया अध्ययन

डॉ. धान्यलक्ष्मी के साथ मोनिश देशपांडे, नीतीश कुमार, अर्पणा रवि,विजेश वि कृष्णा व मेहा जैन ने सहयोग दिया है। विज्ञानियों ने भारत के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में करीब ढाई साल तक अध्ययन किया।

ऐसे कर सकते हैं सुधार

- खेती के तकनीक में सुधार लाकर इससे बच सकते हैं।
- शून्य जुताई का उपयोग कर कृषि अवशेष का उपयोग खेतों में ही करके खाद बनाया जा सकता है।
- अवशेषों से जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना आदि शामिल है।
- कुछ राज्यों में इस तकनीक का उपयोग कर कृषि अवशेष जलाने में कमी आई है।
- किसानों को प्रशिक्षित कर तकनीक का उपयोग कर कृषि अवशेष को जलाने से बच सकते हैं।
- यह तकनीक इस गंभीर पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए क्षेत्र-विशेष के लिए रणनीतियों और नीतिगत हस्तक्षेपों को तैयार करने के लिए प्रमाण आधारित समाधान प्रदान कर सकती है
- भारत में हर साल 87 मिलियन टन कृषि अवशेष जलाए जाते हैं। इससे पर्यावरण प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसे रोकने के उपाय करने होंगे।
- वर्ष 2014-2015 में प्रभावी रूप से नीति क्रियान्वयन के कारण फसलों के अवशेषों के जलने में प्रारंभिक रूप से कमी आई थी, जबकि वर्ष 2016 में फिर से इसमें वृद्धि देखी गई है।

समूह की 14 महिलाओं पर दर्ज हो चुका केस

सतना में गेहूं खरीदी केंद्र में 56 लाख का घोटाला

सतना। जागत गांव हमार

हाल ही में जिले के अरगट रामनगर गेहूं खरीद केंद्र में 56 लाख का बड़ा घोटाला सामने आया है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर रामनगर पुलिस ने स्वसहायता समूह की 14 महिलाओ और खरीद केंद्र के कम्प्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि स्वसहायता समूह की मिलीभगत से कम्प्यूटर ऑपरेटर ने 18 किसानों के नाम पर फर्जी कागजो में 27 सौ क्विंटल गेंहू खरीद लिया। साथ ही कागजों पर ही 56 लाख रुपए का भुगतान कर दिया।

पुलिस में रिपोर्ट दर्ज

एफसीआईने पुलिस में रिपोर्ट कर घोटाले का भंडाफोड़ कर दिया है। इसक मामले में 14 महिलाओं व अरगट गेहूं खरीद केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर रामसकल सिंह के खिलाफ मामला कायम किया गया है। विपणन वर्ष 2023/24 में रामनगर के अरगट गेहूं खरीद केंद्र में लक्ष्मी सहायता समूह सुलखमा को गेहूं खरीद का संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी।

18 फर्जी किसान

गेहूं खरीद केंद्र ने कुल 8981.5 क्विंटल गेहूं खरीद की थी। 6300 क्विंटल गेहूं परिदान कर दिया गया था। शेष बचे 2681.5 क्विंटल गेहूं खरीदा ही नहीं गया था। लक्ष्मी स्वसहायता समूह की मिलीभगत से घोटाले को अंजाम देते हुए वगैर गेंहू के ही कंप्यूटर ऑपरेटर रामसकल सिंह ने खरीद पोर्टल में 18 फर्जी किसानों के नाम से एंट्री कर दी।

भुगतान पर रोक

2681.5 क्विंटल गेहूं के 56,98,187 रु. किसानों के खाते में ट्रांसफर भी कर दिए गए थे। 10 किसानों ने भुगतान भी प्राप्त कर लिया था। लेकिन मामले का खुलासा होने पर 8 किसानों के भुगतान पर रोक लगा दी गई है।

आधा इंच कम बरसा: 46 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश

मध्यप्रदेश से पांच साल में सबसे जल्दी लौटा मानसून

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश से मानसून पूरी तरह विदा हो गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। 5 साल में ऐसा पहली बार हुआ, जब मानसून जल्दी लौटा हो। इस बार सामान्य से सिर्फ आधा इंच बारिश कम हुई है। 46 जिले ऐसे हैं, जहां 80 प्रतिशत से 148 प्रतिशत तक बारिश हुई है। इस बार इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, झाबुआ, रतलाम, नरसिंहपुर, सिवनी और भिंड ऐसे जिले हैं, जहां पर 120 प्रतिशत से अधिक बारिश हुई है।

प्रदेश में 24 जून को मानसून की एंट्री हुई थी। जून में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन जुलाई और अगस्त में आंकड़ा माइनस में रहा था। सितंबर में 70 प्रतिशत अधिक बारिश हो गई थी। इससे सामान्य बारिश का आंकड़ा बराबरी पर आ गया। हालांकि, छह जिले ऐसे रहे, जहां 80 प्रतिशत से कम बारिश हुई। जिससे यह रेड जोन की कैटेगरी में आ गए।

इस साल ऐसा रहा मानसून का दौर

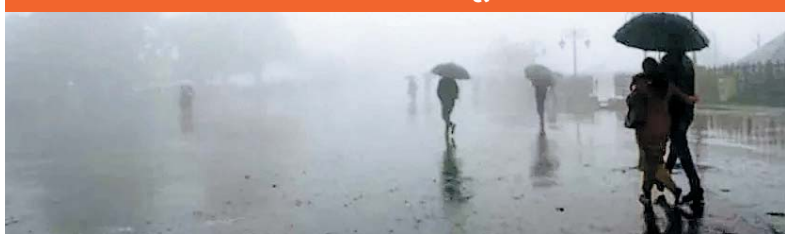

इस बार मानसून ने कई उतार-चढ़ाव देखे। अगस्त में 40 प्रतिशत तक कम बारिश हो गई। इससे प्रदेश में सूखे जैसी तस्वीर सामने आ गई। मंदिरों में प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया। सितंबर के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाकाल मंदिर उज्जैन में विशेष अनुष्ठान तक कर दिया। आखिरकार सिस्टम एक्टिव हुआ, जिसने प्रदेश को सूखे से बाहर निकाल दिया। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एसएच पांडे ने बताया कि जून में विपरजॉय के असर से प्रदेश में अच्छी बारिश हो गई। इस महीने सामान्य से 14 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई, लेकिन जुलाई में यह आंकड़ा 2 प्रतिशत कम हो गया, जबकि जुलाई में तेज बारिश होने का पैटर्न रहता है। अगस्त में भी तेज बारिश होती है, लेकिन इस महीने 3 बार मानसून ब्रेक रहा। इससे प्रदेश में 40 प्रतिशत तक बारिश कम हुई। सितंबर में मानसून विदाई लेता है, लेकिन 2 दौर ऐसे आए कि प्रदेश को सूखे से बाहर निकाल दिया। सामान्य से 70 प्रतिशत बारिश ज्यादा होने से प्रदेश में डैम, तालाब ओवरफ्लो हो गए और नदियां उफान पर आ गईं। सिस्टम ने पूरे प्रदेश को भिगो दिया।

9 जिलों में 120% से ज्यादा बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, कम-ज्यादा बारिश की 3 कैटेगरी हैं। इनमें 6 जिले ऐसे रहे, जहां 80 प्रतिशत से कम बारिश हुई। इस कारण यह जिले रेड जोन में आ गए। इनमें गुना, अशोक नगर, दमोह, सतना, रीवा और सीधी शामिल हैं। 9 जिलों में 120 प्रतिशत या इससे अधिक बारिश हुई। इनमें इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, झाबुआ, रतलाम, नरसिंहपुर, सिवनी और भिंड जिले शामिल हैं। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत प्रदेश के 37 जिलों में 80 प्रतिशत से लेकर 120 प्रतिशत तक बारिश हुई। मौसम विभाग सामान्य से 20 प्रतिशत कम/ज्यादा बारिश को सामान्य बारिश की कैटेगरी में ही रखता है।

30 साल में किसानों को आपदाओं से 316.4 लाख करोड़ का नुकसान

पिछले तीन दशकों में किसानों को आपदाओं के चलते करीब 316.4 लाख करोड़ रुपए (380,000 करोड़ डॉलर) का नुकसान उठाना पड़ा है। यानी इन आपदाओं के कारण किसानों को हर साल फसलों और मवेशियों के रूप में औसतन 10.24 लाख करोड़ रुपए (12,300 करोड़ डॉलर) की चपत लग रही है। जो कृषि के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का करीब पांच फीसदी है। यह जानकारी खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी नई रिपोर्ट, द इम्पैक्ट ऑफ डिसास्टर्स ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में सामने आई है, जिसे 13 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि प्रमुख कृषि उत्पादों का होता नुकसान भी बढ़ रहा है।

पिछले 30 वर्षों के दौरान अनाज को हर वर्ष औसतन 6.9 करोड़ टन का नुकसान हो रहा है, जो 2021 में फ्रांस में अनाज की कुल पैदावार के बराबर है। इसी तरह फल, सब्जियों और गन्ने की फसलों में सालाना करीब चार करोड़ टन का नुकसान दर्ज किया गया, जो 2021 में जापान और वियतनाम में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन के बराबर है। इन आपदाओं से हर वर्ष औसतन 1.6 करोड़ टन मांस, अंडे और डेयरी उत्पाद बर्बाद हो रहे हैं जो मैक्सिको और भारत में 2021 में हुए इनके कुल उत्पादन से मेल खाता है।

कमजोर देशों में किसानों को ज्यादा नुकसान: यदि देशों और क्षेत्रों के आधार पर देखें तो इस नुकसान में काफी अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार इन आपदाओं से कुल को सबसे ज्यादा एशिया में नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका की बारी आती है। हालांकि जहां एशिया में यह नुकसान कृषि मूल्य का केवल चार फीसदी था, वहीं अफ्रीका में, वो करीब आठ फीसदी दर्ज किया गया। इसी तरह यदि उप-क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो यह अंतर और भी बड़ा था।

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि तीन दशकों में आपदाओं ने तुलनात्मक रूप से निम्न और निम्न से मध्यम आय वाले देशों में कृषि को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जो उनके कृषि के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 15 फीसदी तक है।

हालांकि यदि कुल घाटे की बात करें तो समृद्ध और मध्यम आय वाले देशों को अधिक नुकसान हुआ। वहीं कम आय वाले देशों, उनमें भी विशेष रूप से छोटे विकासशील द्वीपीय देशों (एसआईडीएस) को भी इससे अच्छा-खासा नुकसान पहुंचा है, जो उनकी कृषि के कुल सकल घरेलू उत्पाद का करीब सात फीसदी है। गौरतलब है कि इस रिपोर्ट में आपदाओं को किसी समाज या समुदाय के कामकाज में गंभीर व्यवधान के रूप में परिभाषित किया है। इनमें प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आक्रामक कीटों के हमले और कोविड-19 महामारी तक शामिल हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार 70 के दशक में इन आपदाओं की संख्या जो हर साल 100 दर्ज की गई थी, वो पिछले 20 वर्षों में 300 फीसदी की वृद्धि के साथ बढ़कर प्रति वर्ष 400 पर पहुंच गई है। देखा जाए तो इन आपदाओं की केवल संख्या ही नहीं आवृत्ति, तीव्रता और जटिलता भी बढ़ रही है। वहीं अनुमान है कि भविष्य में हालात और बदतर हो सकते हैं, क्योंकि जलवायु संबंधी आपदाएं समाज और पर्यावरण में पहले से मौजूद समस्याओं को और बदतर बना देती हैं।

यह अपनी तरह की पहली बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें एफएओ ने फसलों और पशुधन से जुड़े कृषि उत्पादन पर आपदाओं के प्रभाव का आंकलन किया है। हालांकि रिपोर्ट ने यह भी माना है कि यदि हमारे पास मछली पालन, जलीय कृषि और वानिकी में हुए नुकसान के पर्याप्त डेटा होता तो नुकसान के यह आंकड़े कहीं ज्यादा होते। रिपोर्ट इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि, जब खतरे प्रकट होते हैं, तो वे कई प्रणालियों और क्षेत्रों को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं। इन समस्याओं के पीछे की वजह जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता, जनसंख्या वृद्धि, महामारी से जुड़ी आपात स्थिति, भूमि का गलत तरीके से होता उपयोग, युद्ध और पर्यावरण को होता नुकसान जैसे कारक होते हैं। किसी आपदा में कितना नुकसान होता है यह इस बात से तय होता है कि खतरा कितना बड़ा और कितनी तेजी से फैलता है। साथ ही स्थिति कितनी कमजोर थी और उनके रास्ते में कितने लोग या संपत्ति आती है उसपर भी निर्भर करता है। कभी-कभी, यह चरम आपदाएं ग्रामीणों को अपना घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर कर देती हैं।

आपदा की तैयारी पर खर्च हर रुपए से किसानों को होगा 600 फीसदी का फायदा: ऐसे में आपदाएं कृषि से जुड़े सभी क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रही हैं, रिपोर्ट इस बारे में आंकड़ों और जानकारी को तेजी से बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। देखा जाए तो यह आंकड़े ऐसे तंत्र के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो आंकड़ों पर आधारित प्रभावी निर्णय लेने में मददगार साबित हो सकता है।

रिपोर्ट की प्रस्तावना में एफएओ के महानिदेशक क्यू डोंगयु ने लिखा है कि, कृषि आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, क्योंकि वो प्रकृति और जलवायु पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। बार-बार आने वाली आपदाएं खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रणालियों की स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनके मुताबिक रिपोर्ट में एफएओ की विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए, इन जोखिमों को संबोधित करने और कृषि प्रथाओं और नीतियों में आपदा जोखिम प्रबंधन को शामिल करने के तरीके सुझाए गए हैं। छोटे किसान जो अपनी फसलों के लिए बारिश पर निर्भर रहते हैं, वो आपदा आने पर मुश्किल में पड़ जाते हैं। देखा जाए तो कृषि खाद्य प्रणालियों की सबसे कमजोर कड़ी हैं। जो इन आपदाओं का सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतते हैं। ऐसे में किसानों को सिखाना की वो अपने खेतों को आपदाओं से कैसे बचा सकते हैं। उनकी फसलों को बचाने में मदद कर सकता है। साथ ही यह उन्हें कहीं ज्यादा सशक्त बनाएगा। इन नए तरीकों का उपयोग, पुराने तरीकों की तुलना में 2.2 गुना ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। जब हमें पता हो कि कुछ बुरा हो सकता है तो समय रहते पहले से की गई कार्रवाई वास्तव में महत्वपूर्ण होती है। यह खेतों को सशक्त बनाने में मदद करता है और समस्याओं को कम करता है। उदाहरण के लिए कुछ देशों में, जब उन्होंने आपदाओं की तैयारी के लिए समय से पहले काम किया, तो उन्हें इसके अच्छे नतीजे भी प्राप्त हुए। रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि की गई है, इन आपदाओं से बचने पर खर्च किए हर एक रुपए से किसान को सात रुपयों का फायदा हुआ है, क्योंकि इसकी वजह से वो फसल को होने वाले नुकसान को कम कर पाए थे।

मांस उत्पादन के लिए नर भैंस बछड़ों को पालने की संभावना

» डॉ. अश्लेशा रानाडे
» डॉ. प्रदीप कुमार सिंह
» डॉ. सुरभि यादव
» डॉ. नम्रता अग्रवाल
-अपोलो कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन
-पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर, मप्र

भारत में दुनिया की भैंसों की आबादी का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा है। जो दूध और मांस के रूप में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भैंसों को लंबे समय से भारत के किसानों द्वारा एक बेहतर दुग्ध उत्पादन पशु के रूप में पोषित किया गया है। ग्रामीण लोगों के जीवन में भैंस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।भैंसों को विशेष रूप से मांस के उद्देश्य से नहीं पाला जाता है केवल मांस उत्पादन के लिए बुढी मादा और नर जानवरों का उपयोग किया जाता है। भैंस उत्कृष्ट दुग्ध उत्पादक हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में भैंस का हिस्सा सभी दुधारू पशु प्रजातियों में सबसे अधिक है क्योंकि यह हमारे देश में उत्पादित कुल दूध का लगभग 55त्न योगदान देता है। भैंस का दूध अन्य घरेलू पशुओं की तुलना में गुणवत्ता और वसा की मात्रा में बेहतर होता है।

भैंस के शरीर के बड़े आकार के कारण मांस पशु के रूप में उपयोग करने की बहुत अच्छी क्षमता है और यह सस्ते मोटे चारा पर रह सकती है। भैंस पालन को सस्ता और आर्थिक रूप से लाभदायक माना जाता है। मांस के लिए भैंस का वध एक माध्यमिक कृषि प्राथमिकता है। युवा भैंस के मांस की गुणवत्ता काफी बेहतर होती है, क्योंकि उनमें वृद्ध जानवरों की तुलना में मांसपेशियों का अनुपात अधिक होता है और वसा का अनुपात कम होता है। उच्चतम गुणवत्ता वाले भैंस के बछड़े को भारत में पड़वा के रूप में जाना जाता है जो 24 महीने से कम उम्र का होता है ।

भारत ने भैंस के मांस उत्पादन में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया 2016 में वैश्विक भैंस मांस उत्पादन का 42.2प्रतिशत हिस्सा था। अगली पंक्ति में पाकिस्तान 23.4प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ मिस्र (10.9प्रतिशत) चीन (9.2प्रतिशत) और नेपाल (4.6प्रतिशत) था। भैंस के मांस उत्पादन में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है उसके बाद आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। वर्ष 2020-21 में भैंस के मांस के प्रमुख निर्यात स्थल हांगकांग, वियतनाम मलेशिया मिस्र इंडोनेशिया थे।

कम कीमत वाले भारतीय भैंस के मांस ने दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य पूर्व के निम्न और मध्यम आय वाले विकासशील देशों में मजबूत मांग पैदा की है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य प्रमुख निर्यातकों की तुलना में इसका अधिकांश भाग अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला है। भारत के मांस का निर्यात बड़े पैमाने पर खर्च की गई और अनुत्पादक डेयरी भैंसों से होता है जिन्हें किसानों द्वारा रखा जाता है जिनमें ज्यादातर छोटे भूमिधारक होते हैं। निर्यात में उछाल ने उनके लिए आय के अवसर पैदा किए हैं। साथ ही इसने 108 मिलियन भैंसों के झुंडों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है जिनका मांस उत्पादन के लिए कम उपयोग किया जाता है।

भैंस के बछड़े - दुग्ध उद्योग के उपोत्पाद: भैंस में प्रजनन के परिणामस्वरूप नर और मादा बछड़े 50प्रतिशत की संभावना के साथ पैदा होते हैं।दूध उत्पादन के लिए मादाबछड़े को पाला जाता है। नर भैंस के बछड़े की उपयोगिता उनकी माताओं के दूध छुड़ाने के बाद बहुत कम होती है और दूध के प्रवाह को उत्तेजित करने के लिए भी इसकी आवश्यकता नहीं होती है।प्रजनन के लिए कृत्रिम गर्भाधान के उपयोग के कारण उनका उपयोग भी कम हो गया है।इसके अलावा चारा और श्रम की बढ़ती लागत के कारण किसान नर भैंस बछड़े को पालने में असमर्थ हैं। इसके अलावा चारा और श्रम की बढ़ती लागत के कारण किसान नर भैंस बछड़े को पालने में असमर्थ हैं। 2012 में मादा बछड़े की आबादी की तुलना में नर बछड़े की आबादी सिर्फ 53.6 प्रतिशत थी जो नर भैंस बछड़ों में लगभग 50 प्रतिशत में देश स्तर पर मृत्यु दर को दर्शाता है । एक स्पष्ट संकेत है कि नर बछड़ों को उदासीन रखा जाता है और उन्हें ठीक से नहीं खिलाया जाता है और एक वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। इसलिए नर बछड़े को भैंस पालन का उपोत्पाद माना जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है।

भैंस के नर बछड़ों को बेकार समझा जाता है। नर भैंस के बछड़े का उत्पादन निरंतर प्रक्रिया है क्योंकि दुग्ध उत्पादन के लिए प्रजनन आवश्यक है। भैंस अपने जीवनकाल में 4 या अधिक बछड़ों को जन्म देती है। कुल मिलाकर दुग्धव्यवसायमें सैकड़ों हजार बछड़े पैदा होते हैं जिनके लिए वास्तव में कोई बाजार नहीं है। इससे बछड़ों की मृत्यु दर अधिक होती है और उन्हें फेंके हुए दामों पर बेचा जाता है। भारत में नर भैंस के बछड़ों को बोझ के रूप में माना जाता है और आवारा जानवरों की तरह छोड़ दिया जाता है। ऐसे जानवरों के मांस को अगर ठीक से पाला जाए तो निर्यात की काफी संभावनाएं हैं ।

यह देखा गया है कि भारत में हर साल लगभग 10 मिलियन भैंस के बछड़ों को उत्पादन प्रणाली से हटा दिया जाता है या उनकी मां के दूध को बचाने की दृष्टि से प्रबंधन प्रथाओं में जानबूझकर लापरवाही के कारण मार दिया जाता है। नर भैंस के बछड़ों को बचाने और पालने से घरेलू चमड़ा उद्योग के लिए अधिक कच्चा माल उपलब्ध होता है और ग्रामीण रोजगार के नए रास्ते खुलते हैं। भैंस के मांस की उच्च मांग के कारण भैंस को अब मांस उत्पादन के रूप में जाना जाता है ।

कृषि में चुनौतियों से निपटने प्रौद्योगिकीय प्रणालियों को अपनाने की जरूरत: डॉ. हिमांशु पाठक

देश में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने तथा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कृषि क्षेत्र निरन्तर प्रगति कर रहा है। परन्तु अधिकांश चुनौतियां भी इसी क्षेत्र में है। कृषि योग्य भूमि का टुकड़े-टुकड़े होना, मृदा और जल संसाधनों की कमी, भू-जल स्तर में गिरावट, जलवायु प्रतिकूलताएं तथा खेत उत्पादों की मार्केटिंग जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकीय प्रणालियों को अपनाने की जरूरत है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा कृषि विश्व विद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। नए-नए अनुसंधान, अल्पावधि में पकने वाली किस्में, कृषि मशीनरी तथा भूमि की सेहत में सुधार किया जा रहा है साथ ही किसानों की सुविधा व लाभ के लिए सूचना तंत्र, डिजिटल प्रौद्योगिकी का विकास और ई-प्लेटफार्म उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये जानकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एवं सचिव डेयर डॉ. हिमांशु पाठक ने दी।

डॉ. पाठक ने बताया कि भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है, बल्कि निर्यात भी कर रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 के लिए कुल खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 3320 लाख टन निर्धारित किया गया है जबकि वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 3305 लाख टन होने का अनुमान है।

महानिदेशक ने बताया भारतीय कृषि अनु. परिषद के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली ने फसल प्रजातियों के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बताया वर्ष 1969 से अब तक राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली द्वारा कुल 5967 फसल किस्में विकसित की गई है इसमें 2943 अनाज की, 975 तिलहन की, 1083 दालों की, 233 चारे की, 538 रेशे वाली, 146 गन्ने की और 49 अन्य फसल किस्में शामिल है।

उन्होंने बताया कि आईसीएआर के प्रयासों से अब तक कुल 87 बायोफोर्टिफाइड किस्मों का विकास किया गया है। इसमें चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, मसूर, मूंगफली, अलसी, सरसों, सोयाबीन, फूल गोभी, आलू एवं अनार फसलों की किस्में शामिल है।

डॉ. पाठक ने बताया कि देश के 86 फीसदी छोटे एवं सीमांत किसानों की उत्पादकता एवं आय में वृद्धि के लिए लगभग 64 बहुउद्देशीय इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम विकसित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पशु चिकित्सा के क्षेत्र में भी संस्थान द्वारा पशुओं में ज्वलंत समस्या लम्पी वायरस की वेक्सीन विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि देश में 113 संस्थानों एवं 74 कृषि वि.वि. के द्वारा आईसीएआर कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान करने में सबसे आगे है।

देश के कर्णधार युवा वर्ग को कृषि क्षेत्र से जोड़ने की आवश्यकता पर बल देते हुए महानिदेशक ने बताया कि आईसीएआर द्वारा युवाओं के वोकेशनल प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को कृषि क्षेत्र में उद्यमी बनाया जा सके।

रासायनिक खाद से बंजर होती जमीन को बचाया

नर्मदापुरम के किसान ने की जैविक खेती खाद भी बनाते हैं, मुनाफा 3.5 लाख रुपए

नर्मदापुरम। जागत गांव हमार

कई किसान अधिक उत्पादन के लिए रसायन उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर नर्मदाचंल में एक किसान ने जैविक खेती कर देशभर में अलग पहचान बनाई है। इससे उनको अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज भी मिला और मिट्?टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती गई। जैविक खेती से किसानों के साथ ही प्रकृति और पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है। नर्मदापुरम जिले के रोहना गांव के किसान रूपसिंह राजपूत के पास करीब 4 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने 13 साल तक रासायनिक खेती की। इससे उनको अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा था। इससे अच्छी गुणवत्ता वाला अनाज भी नहीं मिल रहा था। 2012-13 में उन्होंने जैविक खेती करने का सोचा। फिर कृषि विभाग से संपर्क कर ट्रेनिंग ली।

धान-गेहूं के साथ सब्जी भी लगाते हैं- किसान रूपसिंह ने जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए साल 2013 में एमपीएसओसीए मप्र भोपाल से जैविक पंजीयन कराया गया। खेत में जैविक पद्धति से खरीफ सीजन में धान, रबी सीजन में गेहूं बोना शुरू किया। जिसमें उन्हें लागत कम और मुनाफा रासायनिक खेती करने जैसा मिला। रूपसिंह पत्ता गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, टमाटर, बैंगन, मैथी, धनिया, पालक, गिलकी, लौकी, चतर फली भी उगाते हैं। इन सब्जियों को इटारसी के सासाहिक जैविक बाजारों में बेचते हैं। ये सब्जियां आसानी से हाथों-हाथ बिक जाती हैं।

रासायनिक खाद से बंजर होने लगी थी जमीन

रूपसिंह राजपूत का कहना है कि रासायनिक उर्वरकों से कुछ सालों तक उत्पादन अच्छा होता है, लेकिन धीरे-धीरे जमीन की उर्वरा शक्तियां कम होने लगती है। धीमी गति से भूमि बंजर होती चली जाती। आखिर में उसमें उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी इंसान को चपेट में ले लेती हैं। जैविक खेती इसके उलट है। गोबर के खाद, वर्मी कम्पोस्ट खाद, बैक्टीरिया खाद के उपयोग से जमीन उपजाऊ होती। इससे उत्पादित अनाज, सब्जियां नुकसानदायक नहीं होती। मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। कृषि भूमि के लिए भी। उन्होंने बताया कि वो मिश्रित खेती करते हैं। एक फसल में नुकसान हो तो दूसरी फसल से आमदनी हो जाती है। साल 2015-16 में परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत निर्मित क्लस्टर में ग्राम रोहना में रूपसिंह सदस्य बने। फिर क्लस्टर समूह के स्क्क (लीड रिसोर्स पर्सन) का दायित्व निभाया। जैविक खेती के साथ-साथ कृषि वानिकी, उद्यानिकी का समावेश और पशुपालन शुरू किया।

जैविक खेती से कम लागत में ज्यादा मुनाफा

रूपसिंह 4 एकड़ में जैविक खेती कर करीब 3.5 लाख रुपए सालाना कमाई कर रहे हैं। साल 2020-21 में 3 एकड़ में जैविक गेहूं और जैविक धान, 1 एकड़ रकबे में जैविक सब्जी का उत्पादन किया। 30 क्विंटल धान से 12 क्विंटल चावल तैयार किए। जिसको 16,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से 1,92,000 रुपए में बेचा। धान में लागत 60 हजार रुपए आई। जैविक गेहूं 9 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से 27 क्विंटल हुआ। जिसे 5500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बेचा। जिससे 1,48,500 रुपए की आय हुई। लागत 45 हजार रुपए आई। 90 हजार रुपए के करीब जैविक सब्जियां पत्ता गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, टमाटर, बैंगन, मैथी, धनिया, पालक, गिलकी और लौकी बेचते हैं। जिसमें लागत 20 हजार रुपए प्रति एकड़ और लाभ 70 हजार रुपए प्रति एकड़ होता है।

खाद और देसी दवा भी बनाते हैं

खेत में रूपसिंह अपनी फसलों को बचाने के लिए बाजार की दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वे गौ-कृपा अमृतम बनाकर उसका छिड़काव करते हैं। 200 लीटर पानी में दो किलो गुड़, दो लीटर छांछ, एक लीटर गौ-कृपा अमृतम का लिक्विड मिलाते हैं। इसी का फसल, सब्जियों पर छिड़काव करते हैं।

तीन महीने में तैयार होती है केंचुआ खाद

जैविक पद्धति से खेती करने में खाद का सबसे अहम योगदान है। केंचुआ खाद पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केंचुआ कीड़ों द्वारा वनस्पतियों और कचरे को विघटित करके बनाई जाती है। वर्मी कम्पोस्ट में बदबू नहीं होती है। मक्खी और मच्छर नहीं बढ़ते हैं। वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। केंचुए को डालने के बाद उसके ऊपर गोबर और कचरा को डाला जाता है। तीन महीने में केंचुआ खाद तैयार हो जाता है।

समझें जैविक खेती के मुनाफे

» रासायनिक खेती में किसानों को खरीफ सीजन में बोवनी की तैयारी के समय कम से कम दो बार जुताई करनी पड़ती है। इसके उलट जैविक खेती में एक बार जुताई करेंगे या नहीं भी करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। इससे बोवनी के समय का खर्च 50 प्रतिशत से भी कम हो जाएगा।

» बोवनी के बाद रासायनिक खेती में खाद डालना जरूरी होता है। ये खाद काफी खर्चीली होती है। जैविक खेती में खाद का खर्च पूरा बच जाता है।

» फसल आने पर कम से कम दो बार रासायनिक खेती में दवाओं का स्प्रे करना होता है। जबकि जैविक खेती में एक बार भी जैविक स्प्रे किया तो खर्च एक चौथाई भी नहीं आता है।

» खरपतवार नष्ट करने में रासायनिक खेती में ज्यादा खर्च होता है। जैविक खेती में मामूली खर्च पर खरपतवार नष्ट की जा सकती है।

» रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती में एक हेक्टेयर में 20 प्रतिशत उत्पादन कम होता है, तो इससे किसान को नुकसान नहीं होता। उसे रासायनिक की तुलना में फसल के दाम ज्यादा मिलते हैं।

» रासायनिक खेती में खाद का खर्च साल दर साल बढ़ता है, लेकिन जैविक में ऐसा नहीं होता है। खेत की स्थिति साल दर साल सुधरती है।

उपलब्धि और पुरस्कार

» साल 2012-13 में 51 हजार रुपए का श्रेष्ठ कृषक पुरस्कार मिला।

» साल 2010-11 में 50 हजार रुपए का राज्य स्तरीय सर्वोत्तम कृषक पुरस्कार।

» साल 2013 में मध्यप्रदेश जैव विविधता संरक्षण के तहत सम्मान, राशि 25000 रुपए मिला।

» साल 2018-19 में मुख्यमंत्री विदेश यात्रा के तहत ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा की।

बोवनी जून-जुलाई यानी बारिश के मौसम में की जा सकती है, लेकिन उचित समय अक्टूबर से नंबवर

धनिया की खेतीः ये किस्में देगी ज्यादा उत्पादन, बाजार में मिलेंगे अधिक दाम

धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण

भोपाल। जागत गांव हमार

मसाला फसलों में धनिया भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धनिया अम्बेली फेरी या गाजर कुल का एक वर्षीय मसाला फसल है। इसका हरा धनिया सिलेन्ट्रो या चाइनीज पर्सले कहलाता है। धनिया के बीज एवं पत्तियां भोजन को सुगंधित एवं स्वादिष्ट बनाने के काम आते हैं। धनिया बीज में बहुत अधिक औषधीय गुण होने के कारण कुलिनरी के रूप में, कार्मिनेटीव और डायरेटिक के रूप में उपयोग में आते हैं।

धनिया की अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्में/धनिया की उन्नत किस्में- धनिया की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों में हिसार सुगंध, आर सी आर 41, कुंभराज, आरसीआर 435, आर सी आर 436, आरसीआर 446, जीसी 2 (गुजरात धनिया 2), आरसीआर 684, पंत हरितमा, सिम्पो एस 33, जे डी-1, एसीआर 1, सीएस 6, जेडी-1, आर सी आर 480, आरसीआर 728 शामिल हैं।

बोवनी का उचित समय - वैसे तो इसकी बुवाई जून-जुलाई, बारिश के मौसम में की जा सकती है, लेकिन इसकी बुवाई का उचित समय अक्टूबर से नंबवर का होता है। इस समय इसकी बुवाई करने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।

जलवायु/गर्मी में हरे धनिया की खेती कैसे करें- शुष्क व ठंडा मौसम अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुकूल होता है। बीजों के अंकुरण के लिए 25 से 26 सेंटीग्रेट तापमान अच्छा होता है। धनिया शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण फूल एवं दाना बनने की अवस्था पर पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है।

सिंचित अवस्था में 15-20 किग्रा/हेक्टेयर बीज तथा असिंचित में 25-30 किग्रा/हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। भूमि एवं बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को कार्बेन्डाजिम+थाइरम (2ः1) 3 ग्रा/किग्रा या कार्बोक्जिन 37.5 प्रतिशत+थाइरम 37.5 प्रतिशत 3 ग्रा/किग्रा+ ट्राइकोडर्मा विरिडी 5 ग्रा./किग्रा बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए बीज को स्ट्रेप्टोमाईसिन 500 पीपीएम से उपचारित करना लाभदायक रहता है।

भूमि का चुनाव

धनिया की सिंचित फसल के लिए अच्छा जल निकास वाली अच्छी दोमट भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होती है और असिंचित फसल के लिए काली भारी भूमि अच्छी होती है। धनिया क्षारीय एवं लवणीय भूमि को सहन नहीं करता है। अच्छे जल निकास एवं उर्वरा शक्ति वाली दोमट या मटियार दोमट भूमि उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 होना चाहिए।

खाद व उर्वरक

असिंचित धनिया की अच्छी पैदावार लेने के लिए गोबर खाद 20 टन/हेक्टेयर के साथ 40 किग्रा नत्रजन, 30 किग्रा स्फुर, 20 किग्रा पोटाश तथा 20 किग्रा सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से तथा 60 किग्रा नत्रजन, 40 किग्रा स्फुर, 20 किग्रापोटाश तथा 20 किग्रा सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचित फसल के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए।

खरपतवार नियंत्रण के उपाय

धनिया में शुरुआती बढ़वार धीमी गति से होती हैं इसलिए निराई-गुड़ाई करके खरपतवारों को निकलना चाहिए। सामान्यत: धनिया में दो निराई-गुड़ाई पर्याप्त होती है। पहली निराई-गुड़ाई के 30-35 दिन में तथा दूसरी 60 दिन बाद करनी चाहिए। इससे बढ़वार अच्छी होने के साथ उत्पादन बढ़ता है। इसके अलावा खरपतवार नियंत्रण के लिए पेन्डीमिथालीन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर 600 लीटर पानी में मिलाकर अंकुरण से पहले छिडक़ाब करना चाहिए।

धनिया की वैज्ञानिक खेती

सिंचित फसल की वैज्ञानिक तकनीकि से खेती करने पर 15-18 क्विंटल बीज एवं 100-125 क्विंटल पत्तियों की उपज तथा असिंचित फसल की 5-7 क्विंटल/हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है।

महाराणा प्रताप विवि का रीजनल सेंटर में शुष्क जमीन पर फल और सब्जियां

अब शुष्क जमीन पर खेती करना होगा आसन, तैयार किए जा रहे हाइब्रिड बीज

झज्जर। जागत गांव हमार

महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी झज्जर जिले के रईया गांव में रीजनल सेंटर बना रही है। करीब 100 एकड़ में बन रहे इस रीजनल सेंटर में शुष्क जमीन पर फल और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने के लिए रिसर्च की जा रही है। झज्जर के रईया गांव की पंचायती जमीन पर वर्ष 2016-17 में इस सेंटर की नींव रखी थी। यहां करोड़ों रुपये की लागत से करीब 100 एकड़ में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर स्थापित किया गया है। इस सेंटर का मकसद शुष्क जमीन पर किसानों के लिए उत्तम क्वालिटी के फलों और सब्जियों के बीज एवं पौध उपलब्ध करवाना है। ताकि देश के कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र में भी पैदावार बढ़ाई जा सके।

किसानों के लिए तैयार किए जा रहे हाइब्रिड बीज

इंचार्ज डॉक्टर एसपी यादव ने कहा कि 2021 में इस सेंटर में काम शुरू हो गया था। अब इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आने लगे हैं। इस केंद्र में किसानों को महीने में दो बार फल एवं सब्जियां उगाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहां भिंडी का ऐसा हाइब्रिड बीज तैयार किया गया है, जिसकी सहायता से किसान भिंडी की दो से तीन गुना ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। यहां बेल वाली सब्जियां जैसे घीया, तोरई, करेला समेत टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और बैंगन की उत्कृष्ट पौध तैयार कर किसानों को दी जा रही है। इतना ही नहीं किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

कई तरह के फलों पर भी रिसर्च जारी

वहीं डॉक्टर सहगुन खान ने कहा कि इस केंद्र में फिलहाल 100 से ज्यादा किस्म के अनार के पौधों पर रिसर्च की जा रही है। जिस किस्म का अनार यहां सबसे ज्यादा पैदावार देगा उसी तरह के अनार के पौधे किसानों को लगाने के लिए दिए जाएंगे ताकि किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें। यहां झज्जर के मशहूर अमरूद के पौधे भी लगाए गए हैं। आगे आने वाले समय में यहां बीकानेरी बेर और अंजीर पर भी रिसर्च की जाएगी। इसके साथ ही कई एकड़ में ड्रेगन फ्रूट लगाने की भी तैयारी की जा चुकी है। साल 2016 में करनाल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। ये उत्तर भारत की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। हरियाणा में इसके अब तक पांच रीजनल सेंटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें झज्जर के अलावा मेवात, फरीदाबाद, रेवाड़ी और भिवानी जिले शामिल हैं।

किसानों को मालामाल कर सकती है सरसों की 5 किस्में

भोपाल। जागत गांव हमार

भारत के लगभग सभी राज्यों में फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक सबकुछ मौसम पर निर्भर होता है। जैसा की आप जानते हैं कि खरीफ की फसलों की कटाई चल रही है। वहीं किसान रबी फसलों को बोने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं रबी फसल में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों में आलू, मटर, सरसों, गेहूं आदि हैं। सरसों की इन उन्नत किस्मों के नाम पूसा बोल्ड, पूसा सरसों 28, राज विजय सरसों-2, पूसा मस्टर्ड 21 और पूसा सरसों आरएच 30 हैं। यह सभी भारत में तिलहन के उत्पादन में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सरसों की किस्में हैं। ये किस्में किसानों को कम लागत के साथ में प्रति हेक्टेयर ज्यादा मुनाफा देती हैं। इनकी पैदावार भी अन्य किस्मों की अपेक्षा ज्यादा होती है।

सरसों पूसा बोल्ड

फसल पकने का समय- 100 से 140 दिन
बुआई का क्षेत्र- राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र क्षेत्र
प्रति हेक्टेयर पैदावार- 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
तेल की मात्रा- लगभग 40 प्रतिशत तक

पूसा सरसों 28

फसल पकने का समय- 105 से 110 दिन
बुआई का क्षेत्र- हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और जम्मू-कश्मीर
प्रति हेक्टेयर पैदावार- 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर
तेल की मात्रा- लगभग 21 प्रतिशत तक

राज विजय सरसों-2

फसल पकने का समय- 120 से 130 दिन
बुआई का क्षेत्र- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के इलाकों में
प्रति हेक्टेयर पैदावार- औसत पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक
तेल की मात्रा- लगभग 37 से 40 प्रतिशत

पूसा सरसों आर एच 30

फसल पकने का समय- 130 से 135 दिनों
बुआई का क्षेत्र- हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र के लिए प्रमुख
प्रति हेक्टेयर पैदावार- 16 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक
तेल की मात्रा- लगभग 39 प्रतिशत तक

पूसा मस्टर्ड 21

फसल पकने का समय- 137 से 152 दिनों। बुआई का क्षेत्र- पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रमुख। प्रति हेक्टेयर पैदावार- 18 से 21 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है।

बचाव के लिए कृमिनाशक दवा देना जरूरी

भैंस के बच्चों की मौत का प्रमुख कारण पेट के कीड़ेः डॉ.एसपी सिंह

नवजात पशुधन को बचाकर कमा सकते हैं लाखों रुपए

भिंड/लहार। जागत गांव हमार

जिले के किसान बहुत बड़ी संख्या में पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जिले के किसान-पशुपालकों द्वारा पशुपालन के अंतर्गत भैंस पालन का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। भैंस पालन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन किसानों की आय का प्रमुख जरिया है, लेकिन देखने में आ रहा है कि किसान भैंस पालन से बहुत अधिक मुनाफा नहीं कमा पा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य वजह भैंस के नवजात बच्चों की मृत्यु दर का बहुत अधिक होना है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र लहार के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. एसपी सिंह ने रोन ब्लॉक के मानगढ़ गांव में किसान-पशुपालकों के बीच में बताया कि जनपद में भैंस के बच्चों में मृत्यु दर 70 से 75 फीदसी तक देखी जा रही है। इसके पीछे प्रमुख वजह किसान-पशुपालकों में जानकारी का अभाव है।

मानगढ़ गांव में कृमिनाशी अभियान चलाया जा रहा

उन्होंने बताया कि पैदा होने के बाद नवजात बच्चों को मां का प्रथम दूध खींस नहीं पिलाना, सही तरीके से नाड़ का नहीं काटा जाना तथा पेट के कीड़े अर्थात कृमिनाशीयों से बचाव नहीं करना प्रमुख वजहों में से हैं। इसमें सबसे प्रमुख पेट में पाए जाने वाले अंत: परजीवी हैं। अत: पशुपालकों को चाहिए कि बच्चा पैदा होने के बाद से ही एक घंटे के भीतर खींस पिलाना शुरू कर दें। सही तरीके से नाड़ को काटे तथा उस पर टिंचर आयोडीन या डिटॉल का प्रयोग करें। डॉ. सिंह ने बताया कि गाय-भैंस के बच्चे मां के पेट से ही कीड़े के लार्वा एवं अंडे लेकर पैदा होते हैं। इसलिए पैदा होने के बाद एक साल के अंदर कम से कम 3 से 4 बार कृमिनाशक दवाएं अवश्य देना चाहिए। जिसके अंतर्गत पहली खुराक पैदा होने के बाद 7 से 10 दिन पर दूसरी खुराक 28 से 30 दिन पर तीसरी खुराक 90 से 95 दिन पर तथा चौथी खुराक 150 से 155 दिन पर देना आवश्यक होता है। यदि पशुपालक इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से अपने बहुमूल्य पशुधन को बचाकर उसे भविष्य की गाय व भैंस बना पाएंगे। उन्होंने बताया कि भैंस पालन में उसका बच्चा ही शुद्ध मुनाफा होता है। यदि भैंस पालक किसान हर साल एक बढ़िया बचा लेता है तो वह 60 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक की एफडीआर सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि कोई भी भैंस की जवान पड़िया ढाई से तीन साल पर गर्भधारण करके बच्चा देने को तैयार हो जाती है। जिसकी कीमत बाजार में 1,00,000 तक ली जा सकती है। डॉ. एसपी सिंह ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा नवजात बच्चों की मृत्यु दर रोकने के लिए मानगढ़ गांव में कृमिनाशी अभियान चलाया जा रहा है।

खेती और पशुपालन की परंपरा बहुत पुरानी

देश में ज्यादा दूध देने वाली भैंस की नस्ल मुर्रा

भोपाल। जागत गांव हमार

हमारे देश में खेती और पशुपालन की परंपरा बहुत पुरानी है। यहां किसान खेती के साथ पशुपालन करके अधिक पैसा कमाने में सक्षम हैं।

यही कारण है कि नई-नई नस्लों की गायों और भैंसों को पाला जा रहा है और उनका दूध बेचा जा रहा है। गाय और भैंस की कई प्रजातियां अधिक दूध देती हैं। ये नस्लें डेयरी उद्योग के लिए बहुत अच्छी हैं। भैंस का दूध गाय के दूध के मुकाबले ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका कारण है कि भैंस का दूध गाय से अधिक गाढ़ा होता है। भैंस की मुर्रा नस्ल ज्यादा दूध देने वाली नस्ल मानी जाती है। देश में बड़ी संख्या में पशुपालक इसे पालते हैं और काफी अच्छा लाभ भी प्राप्त करते हैं।

इसके अलावा इस भैंस की दूध देने की क्षमता भी अन्य नस्लों से ज्यादा होती है। मुर्रा नस्ल की भैंस का कलर स्याह काला होता है। इसके अलावा इसके सींग भी घुमावदार होते हैं।

एक दिन में मिलता है 20 से 30 लीटर दूध

मुर्रा भैंस का सिर छोटा और पूंछ लंबी होती है। साथ ही इसका पिछला हिस्सा सुविकसित होता है। इस भैंस का सिर, पूंछ और पैर पर सुनहरे रंग के बाल भी मिलते हैं। मुर्रा भैंस की गर्भावधि करीब 310 दिन की होती है। अगर इसकी अच्छी देखभाल हो तो ये भैंस हर दिन में 20 से 30 लीटर तक दूध देती है।

इतनी होती है भैंस की कीमत

पशुपालकों को इस भैंस के दूध के भाव भी काफी अच्छे मिलते हैं। मुर्रा भैंस के दूध की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत बाजार में काफी अच्छी है। इस भैंस की कीमत 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक होती है।

बकरी पालन को मिलेगा बढ़ावा: प्रस्तावित किए गए ज्ञापन समझौते पर दोनों ही तरफ से हस्ताक्षर भी हो चुके

आईसीएआर-सीआईआरजी का हेइफर इंडिया के साथ समझौता

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

भारत में गरीबों की गाय कही जाने वाली बकरी का पालन आमतौर पर पहले छोटे किसानों के द्वारा किया जाता था। हालांकि, अब इसे बिजनेस के तौर पर बड़े किसानों के द्वारा भी किया जाने लगा है। वहीं, वक्त के साथ बकरियों के दामों में काफी हद तक उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। जिससे इनका पालन कर रहे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर आईसीएआर-सीआईआरजी ने बकरी के मूल्यों पर स्थिरता बनाए रखने के लिए गैरसरकारी संगठन हेइफर इंडिया के साथ समझौता किया है। इस समझौते के मुताबिक बकरियों के उत्पादन को बढ़ाने, उनकी प्रजनन और स्वास्थ्य पर ध्यान केन्द्रित करने और उनके दामों को स्थिर रखने का प्रयास किया जाएगा।

मौजूदा स्थितियों को देखते हुए आईसीएआर-सीआईआरजी ने यह समझौता एक गैरसरकारी संगठन हेइफर इंडिया के साथ किया है। इसके लिए प्रस्तावित किए गए ज्ञापन समझौते पर दोनों ही तरफ से हस्ताक्षर भी हो चुके हैं।

बकरी प्रजनन पर भी देंगे ध्यान

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने इस समझौते के लिए एक गैर सरकारी संगठन हेइफर इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। जिसके लिए दोनों ही संस्थाओं ने हाल ही में ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। इस समझौते के अंतर्गत सरकार की मंशा बकरी पालन को बढ़ावा देने के साथ ही बकरी प्रजनन और स्वास्थ्य पर ध्यान देना है।

समझौते का मिशन उत्पादन में वृद्धि

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के अनुसार इस समझौते के बाद बकरि यों के उत्पादन में वर्तमान की अपेक्षा वृद्धि तो होगी ही इसके साथ ही कई तरह के नए ग्रामीण रोजगारों को भी बढ़ावा मिलेगा। आईसीएआर-सीआईआरजी के अनुसार बकरी पालन उद्योग से सबसे ज्यादा छोटे किसान जुड़े हुए हैं। यह उद्योग बहुत से किसानों की जीवन रेखा का भी काम कर रहा है। ऐसे में बकरियों की कीमतों में अस्थिरता इनके जीवन में कई तरह की परेशानियों को खड़ा करती है। लेकिन सरकार के इस समझौते के बाद बकरी पालन को और बढ़ावा दिया जा सकेगा। हेइफर इंडिया और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद -केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, दोनों ही छोटे किसानों और पशु चिकित्सकों को इस मुहिम का प्रमुख हिस्सा मानते हुए कई तरह के प्रशिक्षण प्रोग्रामों को चलाएंगे।

नवरात्रि: यह एक टेस्टिंग विधि है... जहां कम जगहों में बीज की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता दोनों की जाती है चेक

जौ के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी

यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितनी पैदावार होगी

भोपाल। जागत गांव हमार

हिंदू धर्म में नवरात्रि के त्योहार का विशेष महत्व है। पूरे वर्ष में चार बार नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अक्टूबर या नवंबर माह में मनाई जाने वाली शरद नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस त्यौहार में जौ या जवार का बहुत महत्व है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के दिन घरों और मंदिरों में जौ बोने का महत्व है। जौ के बिना नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि में जौ क्यों बोया जाता है? जानिए इसका रहस्य और इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं।

हिंदू धर्म में जौ को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया, तो वनस्पतियों के बीच उगने वाली पहली फसल जौ या ज्वार थी। इसे पूर्ण फसल भी कहा जाता है। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोने का भी महत्व है। जौ बोने के साथ ही कलश स्थापना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में जौ बोने से देवी भगवती प्रसन्न होती हैं और देवी दुर्गा के साथ-साथ देवी अन्नपूर्णा और भगवान ब्रह्मा का भी आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में बोए गए जौ के उगने के बाद उससे शुभ और अशुभ संकेतों का पता लगाया जाता है। इसके अलावा देवी-देवताओं की पूजा, हवन या किसी विशेष अनुष्ठान के दौरान भी जौ अर्पित किए जाते हैं।

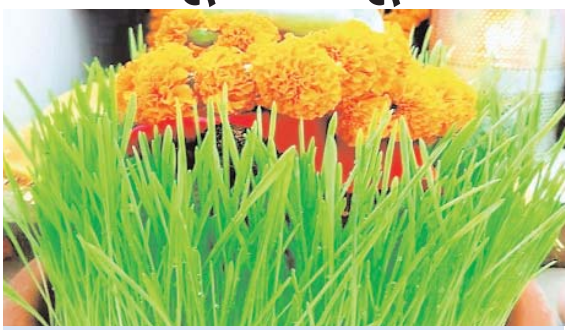

क्या है इसके पीछे का कान्सैप्ट| रबी मौसम में जौ बोया जाता है। अर्थात जौ की बुआई अक्टूबर माह में प्रारम्भ हो जाती है। ऐसे में लोग नवरात्रि से पहले सबसे पहले जौ के बीज बोते हैं और यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस साल कितनी पैदावार होगी। इसके अलावा, भगवान को एक तरह का प्रसाद भी लगाया जाता है। ताकि फसल पर भगवान की कृपा बनी रहे। यह एक टेस्टिंग विधि है। जहां कम जगहों में बीज की उपजाऊ क्षमता और गुणवत्ता दोनों चेक की जाती है।

नवरात्रि में जौ उगाने का आसान तरीका

सबसे पहले जौ के बीजों को 6-8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखें। एक छोटा बर्तन या ट्रे लें और उसे मिट्टी या बालू से भर दें। भीगे हुए जौ के बीजों को मिट्टी पर समान रूप से छिड़कें और उन्हें मिट्टी या बालू की एक पतली परत से ढक दें। मिट्टी/बालू को धीरे से पानी दें, ध्यान रखें कि बीजों को नुकसान न पहुंचे। बर्तन या ट्रे को धूप वाले स्थान पर रखें, या खिड़की के पास जहां उसे सूरज की रोशनी मिल सके। मिट्टी/बालू को पूरी तरह सूखने से बचाने के लिए नियमित रूप से पानी दें। कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे कि जौ के बीज अंकुरित होने शुरू हो जाएंगे। अंकुरों को नियमित रूप से पानी देना जारी रखें, और लगभग 7-10 दिनों में, आपके पास पूरी तरह से विकसित जौ के अंकुर उपयोग के लिए तैयार होंगे।

20 से अधिक एफपीओ के उत्पादों की प्रदर्शनी

किसानों को बढ़ावा देने दिल्ली में एफपीओ मेला आयोजित

भोपाल/नई दिल्ली। जागत गांव हमार

कृषि मंत्रालय, लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी) और सीएससी ने मिलकर आइएनए मार्केट स्थित दिल्ली हॉट में एफपीओ मेले का आयोजन किया। इस मेले में देश के प्रमुख एफपीओ ने भाग लिया। दिल्ली हाट में लगे इस मेले में 20 से अधिक एफपीओ को एक से बढ़कर एक उत्पादों की प्रदर्शनी हुई। इस मेले के माध्यम से आने वाले लोगों को प्राकृतिक उत्पादों का एक नया अनुभव मिला।

एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन, किसानों का एक समूह होता है जो अपने क्षेत्र में फसल उत्पादन से लेकर खेती-किसानी से जुड़ी तमाम व्यावसायिक गतिविधियां भी चलाता है। एफपीओ के जरिए किसानों को ना सिर्फ कृषि उपकरण के साथ खाद, बीज, उर्वरक जैसे कई उत्पाद के थोक मूल्य पर छूट मिलती है, बल्कि एफपीओ तैयार फसल एवं उसकी प्रोसेसिंग करके उत्पाद को मार्केट में बेचते हैं। गौरतलब है कि एफपीओ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार दे रहे है।

8 लाख किसान एफपीओ के साथ कर रहे व्यापार

सभी किसानों की बाजार तक पहुंच आसान बनाने के क्रम में मंगलवार को देश के हर ब्लॉक में एक एफपीओ या तो बन चुका है या जल्द ही बन जाएगा। एफपीओ के माध्यम से मंगलवार को 8 लाख किसानों के 2165 से ज्यादा संगठन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ जुड़कर व्यापार कर रहे हैं। इस मौके पर सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक और सीईओ, संजय राकेश ने कहा कि सीएससी ने हमेशा विभिन्न पहलों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। किसान और कृषि हमारी पहल का अभिन्न अंग हैं। देश के दूर-दराज इलाकों में मौजूद सीएससी के विशाल नेटवर्क की बदौलत पहले से ही हम किसानों को टेली-परामर्श, फसल बीमा, ई-पशु चिकित्सा, किसान क्रेडिट कार्ड और पीएम किसान योजनाओं के जरिए विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम देश भर में एफपीओ के गठन में पूरे जोश के साथ काम कर रहे हैं। एफपीओ के जरिए हमारे देशभर के किसानों के सशक्तिकरण में भूमिका निभा रहे हैं।

सीएससी ने बदला ग्रामीण नागरिकों का जीवन

देश के दूरदराज इलाकों में स्थित साढ़े पांच लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर ने नागरिकों के जीवन में एक सराहनीय बदलाव किया है। ग्रामीण नागरिक इन केंद्रों के माध्यम से अपने घर पर ही विभिन्न विभागों की सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम हैं। उदाहरण के लिए, जाति, आय, अधिवास, चरित्र प्रमाण पत्र, और रोजगार पंजीकरण, आदि, इन सेवाओं की मदद से, एफपीओ ने गांव के लोगों को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में मदद करके एक उल्लेखनीय कार्य किया है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में 12 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसान हैं, जिनकी औसत जोत का आकार 1.1 हेक्टेयर से कम है। अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों को उत्पादन और उत्पादन के बाद के काम जैसे टेक्नोलॉजी तक पहुंच, उचित कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण साजो-सामान, बीज उत्पादन, खेती की मशीनरी की इकाई, मूल्य वर्धित उत्पाद, प्रसंस्करण, ऋण, निवेश और सबसे महत्वपूर्ण बाजार दोनों में जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, एफपीओ के गठन के माध्यम से ऐसे उत्पादकों का सामूहिकीकरण ऐसी चुनौतियों का समाधान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

मक्का की नई किस्म, प्रति हेक्टेयर में 70 क्विंटल होगा उत्पादन, किसानों को फायदा

भोपाल। जागत गांव हमार

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमपीयूएटी) ने 'प्रताप-6' नाम से संकर मक्का की नई किस्म विकसित की है। दावा ये कि इससे प्रति हेक्टेयर यानी करीब सात बीघा में 70 क्विंटल तक उपज मिलेगी। मक्का प्रोजेक्ट के प्रभारी और प्रताप 6 के जनक डॉ. आरबी दुबे ने बताया कि यह पीले दाने वाली मक्का की 80 से 85 दिन में पकने वाली किस्म है। खास बात ये भी है कि इसका तना सड़न, रोग, सूत्र कृमि और छेदक कीट के प्रति रोगरोधी है। अभी इस किस्म को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। देश में मौजूदा मक्का की किस्म से इतनी ही भूमि पर औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन 33 क्विंटल है, जबकि प्रदेश में 28 क्विंटल तक है।

मवेशियों के लिए भी फायदेमंद

इस किस्म का मक्के का पौधा पकने के बाद भी हरा रहता है। इससे किसानों को मवेशियों के लिए अच्छी गुणवत्ता का चारा भी मिलेगा। अभी उदयपुर में 1.50 लाख, प्रदेश में 9 लाख, जबकि देशभर में करीब 90 लाख हेक्टेयर में मक्के की खेती की जाती है। अनुसंधान निदेशक डॉ.अरविंद वर्मा ने बताया कि प्रताप 6 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित किया जा चुका है। अब इसके नोटिफिकेशन के लिए जाती है।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)